सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक: 18 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार 19 फरवरी, 2026
मूल्य ₹ 3/-

अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए।
-अब्राहम लिंकन

भारत की विश्वकप में लगातार 12वीं... 7 | बंगाल में फिर मुस्लिम फैक्टर होगा... 3 | भाजपा पीडीए को बदनाम कर... 2

एपस्टीन फाइल्स के साये में एआई समिट

एआई समिट को बिल गेट्स ने बोला बाय

कीनोट स्पीकर के तौर पर गेट्स को समिट में देना था व्याख्यान

» ऐन मौके पर हटाया गया नाम, हाल ही में एपिस्टीन फाइल्स में आया था नाम

» नहीं रूक रहा विवादों का साया, गलगोटिया युनिवर्सिटी ने समिट का घोट दिया गला

» पीएम मोदी ने किया औपचारिक उद्घाटन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से विवादों का साया कम होन का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा विवाद टेक टायकून बिल गेट्स को लेकर सामने आया है। समिट में बिल गेट्स की शिरकत की नोट स्पीकर के तौर पर होनी थी। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने समिट में शामिल होने से मना कर सनसनी फैला दी है। समिट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होने के बावजूद आखिरी समय में लिए गए इस फैसले ने वैश्विक स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी जगह फाउंडेशन के भारत-अफ्रीका प्रमुख अंकुर वोरा समिट में बोलेंगे।

कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि समिट का फोकस एआई के मुख्य मुद्दों पर बना रहे।

ऐन मौके पर पीछे हटने का मतलब

हालांकि गेट्स फाउंडेशन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में समिट की प्राथमिकताओं का हवाला दिया गया है लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की असली वजह जेफरी एप्स्टीन विवाद का दोबारा गहराना है। हाल ही में सार्वजनिक हुई एप्स्टीन फाइल्स और उनमें गेट्स के नाम के उल्लेख ने टेक टाइकून की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जेफरी एप्स्टीन एक सजायाफ्ता यौन अपराधी था जिसके नेटवर्क में दुनिया के कई रसूखदार लोग शामिल थे। नए अदालती दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों के सामने आने के बाद गेट्स के पुराने संबंधों को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं।

बिल गेट्स का सम्मिट से हटने को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले गेट्स फाउंडेशन की ओर से कहा गया कि बिल गेट्स की नोट देंगे। फिर अचानक अगले ही दिन कहा गया कि वह की नोट नहीं देंगे और उनका नाम आधिकारिक वेबसाइट से भी हटा दिया गया पूरा घटनाक्रम बेहद संदिग्ध लग रहा है। माइक्रोसाफ्ट के को—फाउंडर बिल गेट्स का सम्मिट से हटने को एपस्टीन फाइल्स से जोड़ कर भी देखा जा रहा है।

एपस्टीन फाइल्स या फिर कुछ और

एपस्टीन फाइल्स को लेकर भारत में भी राजनीति तेज है और इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ऐसे महौल में यदि गेट्स बोलते तो निश्चित तौर पर उन आशंकाओं को बल मिलता जो हवा में तैर रही है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें कार्यक्रम से दूरी बनाने के लिए कहा गया। सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह आशंका भी व्यक्त की जाने लगी कि गेट्स की उपस्थिति से समिट का फोकस एआई और तकनीकी सहयोग से हटकर एपस्टीन विवाद पर केंद्रित हो सकता है। ऐसे माहौल में यह भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम की गरिमा और भारत की वैश्विक छवि को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उन्हें दूरी बनाने की सलाह दी गई। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन जिस तरह अचानक उनका कीनोट रद्द हुआ और उनका नाम प्रमुख वक्ताओं की सूची से हटया गया उसने इन अटकलों को और बल दे दिया है। राजनीतिक रूप से भी यह मामला संवेदनशील बन गया है क्योंकि भारत इस समय खुद को वैश्विक एआई नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद से जुड़ा नाम इस महत्वाकांक्षी नैरेटिव को कमजोर कर सकता था। यही वजह है कि कई जानकार इसे एक रणनीतिक और नियंत्रित निर्णय मान रहे हैं ताकि तकनीकी मंच को राजनीतिक और विवादास्पद छाया से दूर रखा जा सके और भारत की उभरती तकनीकी छवि पर कोई स्थायी धब्बा न लगे।

लेकिन सवाल उठता है कि एपस्टीन फाइल्स का धुंआ पिछले लंबे समय से है ऐसे में यदि इस पहलू को शामिल किया जाए तो फिर उनका नाम समिट में जोड़ा ही क्यों गया? उनको की नोट स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा ही क्यों गया?

पीएम ने किया उद्घाटन

पीएम नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट- 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया। पीएम मोदी का संबोधन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा बल्कि समावेशिता के एक नए संदेश के रूप में भी सामने आया। इस दौरान पहली बार उनके पूरे भाषण का रियल टाइम में सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) में लाइव ट्रांसलेशन किया गया जिससे श्रवण बाधित समुदाय भी सीधे प्रधानमंत्री के विचारों और भारत के एआई विजन से जुड़ सका। समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एआई रणनीति डिजिटल क्षमता और भविष्य की तकनीकी दिशा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में देश और दुनिया के तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत को एआई इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए।

भाजपा पीडीए को बदनाम कर रही : अखिलेश

» बोले- चुनाव आयोग धांधलियों पर कार्रवाई करे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर एकबार फिर करारा प्रहार किया है। सपा मुखिया ने बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नौजवानों में फूट डाल रही है और पीडीए को बदनाम कर रही है। गोरखपुर के स्वास्थ्य मुद्दे पर सरकार को घेरा। चुनाव आयोग से धांधलियों पर कार्रवाई की मांग भी की। समाजवादी पार्टी के विरोध प्रचार की नीति बना रही है।

समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को भाजपा से सावधान रहना है। अखिलेश प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा डॉ. राम मनोहर लोहिया और डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने के लिए अडिग है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा सिर्फ विध्वंस करना जानती है।

गोरखपुर में चिराग तले अंधेरा है

गोरखपुर में रोशनी जाना बनेगा स्वास्थ्य मंत्री का विभाग छीनने का आधार अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छिन रही है। मुख्यमंत्री जब गोरखपुर आते हैं तो क्या और कोई भी देखभाल या हिसाब-किताब करते हैं या फिर केवल जोड़-गांठ करके चले जाते हैं। यहां तो चिराग तले अंधेरा है। स्वास्थ्य मंत्री को भी यह यह समझ लेना चाहिए कि इसे अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उनसे विभाग छीनने का आधार बनाया जा रहा है।

पीडीए के वोट काटने के मुद्दे पर सपा पहुंची चुनाव आयोग

सपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रदेश में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) और विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से काटने की शिकायत की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसा सुल्तानपुर, सिकंदरपुर, सरोजनीनगर, जसवंतनगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, सकलडीहा, विधूना, नगीना, नहटौर, भोजीपुरा, फर्रूखाबाद, मथुरा, कुंदरकी और शामली विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया गया है। फर्जी हस्ताक्षर और दबाव के माध्यम से फार्म-7 जमा किए जा रहे हैं।

फर्जी हस्ताक्षर के प्रयोग से भरवाए जा रहे फार्म-7

सपा का आरोप है कि भाजपा द्वारा सुनियोजित तरीके से पीडीए और मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। कई स्थानों पर निरक्षर व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर का प्रयोग किया गया है, जबकि कुछ मामलों में बीएलओ पर दबाव बनाकर या जबरन हस्ताक्षर करवाकर फार्म-7 जमा कराए गए हैं। जसवंतनगर में एक बीएलओ ने भाजपा नेताओं पर जबरन हस्ताक्षर कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी है। इसी तरह, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी बीएलओ और मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार और धमकी की घटनाएं सामने आई हैं।

चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल

ज्ञापन में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार शिकायतें और ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग, प्रशासन और भाजपा के गठजोड़ से लॉजिकल एरर के नाम पर पीडीए मतदाताओं को नोटिस भेजने का नया खेल खेला जा रहा है। पार्टी ने मांग की है कि फार्म-7 से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी बीएलओ द्वारा ही शुरू की जाए और प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से डाटा जारी किया जाए कि किस विधानसभा क्षेत्र, किस बूथ पर, किसके नाम से फार्म-7 जमा हुआ और किसने किस आधार पर आवेदन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा। फॉर्म-7 पर बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और मतदाता व आवेदक को नोटिस रिसीव कराई जाएगी। इस अवसर पर विधायक कमाल अख्तर, डॉ. आरके वर्मा , मनोज पारस, शहजिल इस्लाम आदि मौजूद रहे। सपा के प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र सिंह यादव और राधेश्याम सिंह ने ज्ञापन की रूपरेखा सामने रखी।

बोराह भाजपा में शामिल होने के बहाने बना रहे : गौरव गोगोई

कांग्रेस नेता बोले- इस्तीफा देने के ठीक एक दिन के भीतर हिमंता बिस्वा सरमा से हाथ मिलाया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गुवाहाटी। असम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नए सिरे से उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। पूरे राज्य में राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। उनकी घोषणा के तुरंत बाद, कुछ स्थानीय पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की थी और अपने फैसले पर पुनर्विचार किया था। इस विवाद पर बोलते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि बोराह भाजपा में शामिल होने के बहाने बना रहे थे।

गोगोई ने कहा कि जब भी कोई भाजपा में शामिल होता है, उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है और उससे उसी के अनुसार बोलने की उम्मीद की जाती है। असम के लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी के भीतर ही समस्याएँ थीं, तो आपने किसी ऐसी पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए जो वास्तव में भाजपा के खिलाफ लड़ रही है? भाजपा का विरोध करने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं। आपने इस्तीफा देने के

ठीक एक दिन के भीतर हिमंता बिस्वा सरमा से हाथ क्यों मिलाया? हालांकि, हालिया घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि बोराह ने वास्तव में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस कदम को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर अपने नए हमले में बोराह ने कहा कि उन्होंने पार्टी को अपने 32 साल दिए, लेकिन गौरव गोगोई के हाथों कई मौकों पर उनका अपमान किया गया। बोराह ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को भी इस बारे में बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को 32 साल दिए।

कांग्रेस ने मुझे विधायक से एपीसीसी अध्यक्ष बनाया। जब मैं 2021 में अध्यक्ष बना, तब कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन में थी। मैंने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद, इंडिया गठबंधन बनने से पहले, मैंने 16 पार्टियों के साथ गठबंधन किया। उपचुनाव में तय हुआ था कि एक सीट सीपीआई (एमएल) को मिलेगी, लेकिन अचानक उसी रात एक ऐसे व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया जो कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं रहा था। गौरव गोगोई वह सीट नहीं जीत सके। 9 फरवरी को गठबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। मुझसे फिर से गठबंधन बनाने को कहा गया... मैंने बातचीत शुरू की।

भाजपा सार्वजनिक करे किसी भी मंत्री ने सोरोस से मुलाकात नहीं की : खेड़ा

» कांग्रेस नेता ने केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू को चुनौती दी कि वे सार्वजनिक रूप से यह घोषित करें कि भाजपा के किसी भी मंत्री ने जॉर्ज सोरोस से मुलाकात नहीं की है, और न ही किसी नेता के बच्चे सोरोस द्वारा वित्तपोषित संगठनों में काम करते रहे हैं या कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी पर अपने सदस्यों को सोरोस से जोड़ने वाले आरोपों को लेकर सवाल उठाए।

खेड़ा ने कहा कि किरेन रिजिजू से कहिए, और मैं उन्हें चुनौती देता हूं, कि वे सार्वजनिक रूप से यह कहें कि भाजपा के किसी भी मंत्री ने सोरोस से मुलाकात नहीं की है। दूसरा, भाजपा नेताओं के बच्चों का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो सोरोस द्वारा वित्तपोषित संगठनों में काम कर रहा हो या कर चुका हो। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। ये टिप्पणियां तब आईं जब रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हालिया राजनीतिक विवादों के बाद उनके व्यवहार को बचकाना और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए उनकी आलोचना की। एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय संसदीय कार्य समिति के नेता ने कहा कि उनका व्यवहार बचकाना और उनकी

स्थिति के हिसाब से गैरजिम्मेदाराना है। विपक्ष का नेता पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सदन से बाहर जाना, लोगों को देशद्रोही कहना, दिखावटी धरने देना और अप्रकाशित पुस्तक पढ़ने पर जोर देना, यह सब बचकाना व्यवहार है। हमने भारत के इतिहास में ऐसा विपक्ष का नेता कभी नहीं देखा।

रिजिजू ने आगे कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं। क्योंकि वे भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। वे देश-विदेश में नक्सलवादियों, चरमपंथियों, विचारधारावादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर संसद की परंपराओं का पालन न करने और कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में शोर-शराबा और हंगामा तो हमेशा होता ही है। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वह उसे सदन में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। यह अपने आप में कोई विफलता नहीं है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

राज्य सरकारों को स्वायत्त निकायों में बदला जाए : स्टालिन

» सीएम की केंद्र को चेतावनी- हम बार-बार झुकने वाले नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में संविधान में संशोधन की मांग करते हुए राज्य सरकारों को स्वायत्त निकायों में बदलने की बात कही और केंद्र पर सारी शक्ति अपने पास रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को ऐसी स्थिति में धकेल दिया गया है जहां उसे अपने हक के फंड पाने के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें हर फंड के लिए केंद्र सरकार से लड़ना पड़ता है। कब तक हम इस स्थिति में रहेंगे जहां वे देते हैं और हम लेते हैं? केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का पहला भाग विधानसभा में पेश कर दिया गया है। स्टालिन ने कहा कि संविधान में संशोधन करके राज्य सरकारों को पूर्ण रूप से सशक्त सरकारों में बदलना होगा।

सभी राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें भूमि और वित्तीय शक्तियों पर अधिकार सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए संघवाद आधारशिला है और राज्य सरकारों के परिवर्तन की मांग को दोहराया। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने राज्य सरकारों का सम्मान किए बिना सारी शक्ति अपने हाथ में ले रखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, जिसने सारी शक्तियां अपने पास रखी हैं, राज्य सरकारों का सम्मान नहीं करती। हम कब तक इस स्थिति में रहेंगे जहां वे देते हैं और हम केवल लेते हैं? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए संघवाद आधारशिला है। सभी राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। हम बार-बार झुकने वाले लोग नहीं हैं। हमें राज्य स्वायत्तता और केंद्र में संघवाद चाहिए; तभी हम सुशासन बहाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल की मांग नहीं है, बल्कि राजनीतिक मतभेदों से परे, सभी को राज्य स्वायत्तता की मांग को स्वीकार करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार, जिसने सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर रखी हैं, राज्य सरकारों का सम्मान नहीं करती।

बंगाल में फिर मुस्लिम फैक्टर होगा चुनाव पर भारी

30 प्रतिशत मुस्लिम वोट, 50 सीटों पर सीधा असर

» किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी ये करेंगे निर्धारित

» ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण पर लड़ाई

» भाजपा व टीएमसी में कड़ी टक्कर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकता। पश्चिम बंगाल में विस चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। सभी सियासी दल गोट बिठाने लगे हैं। जहां भाजपा हिंदुत्व के जरिये ध्रुवीकरण करने की योजना पर काम कर रही है। वहीं सत्ताशीन टीएमसी सेक्यूलिरिज्म के सहारे चौथी बार राज्य पर शासने करने के मंसूबे बना रही है।

कुल मिलकार ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण के ईर्दगिर्द चुनाव हाने की संभावना प्रबल हो रही है। राज्य की राजनीति में तथाकथित मुस्लिम फैक्टर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। मतदाताओं की एक बड़ी संख्या होने के कारण, मुस्लिम मतदाताओं को कई निर्वाचन क्षेत्रों में संभावित किंगमेकर के रूप में देखा जाता है।

केवल 292 सीटों पर ही चुनाव क्यों कराए गए

मुर्शिदाबाद जिले की दो विधानसभा सीटों - शमशेरगंज और जंगीपुर - पर मतदान नहीं हो सका क्योंकि मतदान से पहले ही उम्मीदवारों का निधन हो गया था। शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रेजाउल हक और जंगीपुर से क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी) के उम्मीदवार प्रदीप नंदी का कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया।

पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है। राज्य विधानसभा में 294 सीटें हैं और लगभग 40 से 50 निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। इनमें से कई निर्वाचन क्षेत्रों में, मतदाताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं, जिससे चुनावी परिणामों को निर्धारित करने में उनका वोट एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है।

2021 विधानसभा चुनावों के परिणाम

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शानदार जीत दर्ज की। 294 सीटों में से 292 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें से टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर आरामदायक बहुमत हासिल किया। पार्टी को लगभग 48 प्रतिशत वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी और उसे 77 सीटें मिलीं। दशकों से बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखने वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस को ऐतिहासिक झटका लगा और वे एक भी सीट जीतने में असफल रहे। गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (आईएसएफ) को एक सीट मिली।

मुस्लिम मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में किंगमेकर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती संकेत अभी से दिखने लगे हैं। राज्य की राजनीति में इस समय सबसे चर्चित मुद्दों में से एक है मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर)।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। इसी बीच, पश्चिम बंगाल की राजनीति में तथाकथित मुस्लिम फैक्टर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। मतदाताओं की एक बड़ी संख्या होने के कारण, मुस्लिम मतदाताओं को कई निर्वाचन क्षेत्रों में संभावित किंगमेकर के रूप में देखा जाता है। आइए उनकी जनसांख्यिकीय शक्ति और राजनीतिक प्रभाव पर एक नजर डालें।

झारखंड में सियासत में तुम्ही से मुहब्बत, तुम्ही से लड़ाई

बिहार चुनाव की तरह झारखंड में भी सियासी उतार-चढ़ाव

» आपस में भिड़े राजद-कांग्रेस-झामुमो

» निकाय चुनाव में एक-दूसरे पर चढ़ाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रांची। झारखंड में सियासी उतार-चढ़ाव जारी है। वहां पर झामूमो, राजद व कांग्रेस में तुम्ही से मुहब्बत, तुम्ही से लड़ाई वाला माहौल चल रहा है। रांची नगर निगम के मेयर के चुनाव में जहां भाजपा अपने प्रत्याशी के प्रचार में दम खम से उतर चुकी है।

वहीं, महागठबंधन की पार्टियां यहां आपस में ही लड़ रही हैं। बता दें कि महागठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस और राजद तीनों ने ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए इस बार कुल 11 उम्मीदवार अपनी ताकत आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि हेमंत सोरेन सरकार में गठबंधन में शामिल दलों, राजद और कांग्रेस ने भी अपने-अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वहीं, एनडीए की ओर से अकेली रोशनी खलखो चुनावी मैदान में हैं। भाजपा संगठन उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह जुटा हुआ है।

महागठबंधन में हो रही फाइट

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से सुजीत आनंद विजय कुजूर के पक्ष में पार्टी का पूरा प्रचार-प्रसार चल रहा है। इसके अलावा, कांग्रेस की ओर से रमा खलखो के समर्थन में मंत्री और विधायक चुनाव प्रचार में लगे हैं, जबकि राजद समर्थित प्रत्याशी सुजाता कच्छप के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहे हैं। इससे महागठबंधन के भीतर ही 'फ्रेंडली मैच' की स्थिति बन गई है। वहीं, झामुमो फिलहाल बैकफुट पर जाकर चुनावी रणनीति बना रही है।

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है रांची मेयर की सीट

रांची मेयर की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और सभी 11 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से ही हैं। खतरा भांपते हुए भाजपा, कांग्रेस और राजद ने वोट बंटवारे को रोकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

ईसाई वोटरों को एकजुट करने में जुटे झामुमो प्रत्याशी

झामुमो के प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद कुजूर को पार्टी का सीधा समर्थन नहीं मिला है, इसलिए वे मुख्य रूप से क्रिश्चियन वोटरों को एकजुट करने में जुटे हैं।

27 फरवरी को आएगा नतीजा

चुनाव में कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनावी दंगल में किसकी जीत होगी, यह 27 फरवरी को होने वाले मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनावी अभियान चला रहे हैं।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

डीपफेक पर लगाम के लिए नियम जरूरी

देश में एआई पर बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली में हो रहा है। इसमें दुनियाभर की कंपनियां भाग ले रही हैं। हालांकि की कुछ अव्यवस्था की खबरें भी आई। इन सबके बीच सवाल उठ रहें है कि क्या डीप फेक कंटेंट की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। डीपफेक से फैलने वाली भ्रामक जानकारी समाज और देश के माहौल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कानूनी, तकनीकी और व्यवहारिक स्तर पर समन्वित प्रयास जरूरी हैं। एआई से तैयार सामग्री पर वॉटरमार्क या मेटाडेटा अनिवार्य किया जाए, ताकि उसकी पहचान संभव हो सके। संदिग्ध फोटो और वीडियो की जांच के लिए रिवर्स इमेज सर्च जैसे साधनों का उपयोग बढ़ाया जाए। सक्रिय मॉडरेशन तकनीक से फर्जी कंटेंट को वायरल होने से पहले हटाया जा सकता है। साथ ही नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। निजी और उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें अनावश्यक रूप से साझा न करें और किसी भी संदिग्ध सामग्री की तुरंत रिपोर्ट करें।

डीपफेक कंटेंट मुख्य रूप से दो तरह का होता है- वीडियो और ऑडियो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से किसी व्यक्ति की शक्ल या आवाज में बदलाव कर ऐसा कंटेंट तैयार कर दिया जाता है, जो देखने-सुनने में असली लगे, लेकिन होता पूरी तरह नकली है। कई बार इसका इस्तेमाल भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने में किया जाता है। इसे रोकने के लिए सख्त नियम बनाना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लाइसेंस व्यवस्था और अनुचित सामग्री पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। निजी जानकारी अनावश्यक रूप से साझा न करें, मजबूत पासवर्ड रखें और किसी भी साइबर अपराध की तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। डिजिटल दौर में डीपफेक तकनीक एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। यह सिर्फ तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि ऐसा औजार है जो सच और झूठ की सीमा को धुंधला कर देता है। इससे किसी व्यक्ति की साख को गहरा नुकसान पहुंच सकता है और समाज में भ्रम व अविश्वास फैल सकता है। इसलिए कड़े कानून और सख्त सजा का प्रावधान जरूरी है, ताकि दुरुपयोग करने वालों पर लगाम लग सके। सोशल मीडिया कंपनियों को उन्नत एआई टूल्स से संदिग्ध सामग्री की पहचान कर उसे तुरंत हटाना चाहिए। साथ ही डिजिटल साक्षरता पर जोर देना होगा, ताकि लोग हर वायरल वीडियो या तस्वीर को बिना जांचे-परखे सच न मानें।

“ डीपफेक से फैलने वाली भ्रामक जानकारी समाज और देश के माहौल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कानूनी, तकनीकी और व्यवहारिक स्तर पर समन्वित प्रयास जरूरी हैं। एआई से तैयार सामग्री पर वॉटरमार्क या मेटाडेटा अनिवार्य किया जाए, ताकि उसकी पहचान संभव हो सके।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

माता-पिता की देखभाल हेतु जवाबदेही सुनिश्चित हो

डॉ. जगदीप सिंह

भारतीय समाज में परिवार की संरचना और मूल्यों का आधार माता-पिता की सेवा और सम्मान रहा है, लेकिन आधुनिक समय में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लाखों युवा विदेशों में बस रहे हैं। यह प्रवास अक्सर परिवारों के लिए आर्थिक उन्नति लाता तो है, लेकिन कई मामलों में बुजुर्ग माता-पिता भारत में अकेले पड़ जाते हैं। उनकी देखभाल, भावनात्मक समर्थन और नियमित संपर्क की कमी से बुजुर्गों की मानसिक और शारीरिक स्थिति दयनीय हो जाती है। हाल ही में राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने विदेश जाने वाले युवाओं द्वारा माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने सुझाव दिया कि विदेश जाने से पहले बच्चों से एक हलफनामा लिया जाए, जिसमें वे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा माता-पिता की देखभाल के लिए देने का वादा करें। इसके साथ ही, हर छह महीने में माता-पिता से 'संतुष्टि प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य हो। ऐसा प्रमाण पत्र न मिलने या शिकायत आने पर बच्चों का पासपोर्ट रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम सप्ताह में एक बार फोन पर माता-पिता का हालचाल पूछना भी बाध्यकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में पिछले वर्ष 500 से अधिक ऐसे मामले सामने आए, जहां विदेश में बसे बच्चों की उपेक्षा के कारण माता-पिता की हालत बहुत खराब हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। विडंबना है कि बच्चे अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं लौटे। यह मुद्दा केवल भावनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी गंभीर है। भारत में पहले से ही 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' लागू है, जो बच्चों को माता-पिता की आर्थिक और भावनात्मक देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाता है। इस कानून के तहत बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं और बच्चों से मासिक भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण रद्द करने की शक्ति भी शामिल है।

हालांकि, यह कानून विदेश में बसे बच्चों (एनआरआई) पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, प्रवर्तन की कमी और संपर्क की दूरी जैसी समस्याएं आड़े आती हैं। कई एनआरआई बच्चे भारत में संपत्ति या बैंक खाते रखते हैं, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। सांसद का प्रस्ताव इसी कमी को दूर करने का प्रयास है। यदि पासपोर्ट

आवेदन या वीजा प्रक्रिया में माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो सकती है, तो यह उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की कमी होती है। कई मामलों में माता-पिता ने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी जमीन-जायदाद बेच दी, कर्ज लिया या अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन बदले में उन्हें अकेलापन और उपेक्षा मिली। भारतीय संस्कृति में 'मातृ-पितृ भक्ति' को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन आर्थिक महत्वाकांक्षा और पश्चिमी जीवनशैली के प्रभाव से यह मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। यह मुद्दा सांस्कृतिक संकट पर भी ध्यान आकर्षित करता है। नि:संदेह, सफलता के पीछे माता-पिता का बहुत बड़ा त्याग होता है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि यह बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा और बच्चों में जिम्मेदारी की भावना जाग्रत करेगा। दूसरी ओर, आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण बताते हैं। वे कहते हैं कि पासपोर्ट रद्द करना या प्रमाण पत्र की बाध्यता जैसे कदम बहुत कठोर हैं, जो प्रवास की स्वतंत्रता को प्रभावित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पासपोर्ट रद्द करने के लिए केवल गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार होते हैं, न कि पारिवारिक मामले। एनआरआई समुदाय का एक हिस्सा इसे भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि भारत में रहने वाले बच्चे जो माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होती। क्या केवल विदेश जाने वालों पर ही यह नियम लागू होगा? इसके बावजूद, प्रस्ताव की व्यावहारिकता पर विचार करना जरूरी है।

यदि सरकार इसे लागू करना चाहती है, तो विदेश मंत्रालय को एनआरआई से जुड़े डेटाबेस को मजबूत करना होगा, भारतीय दूतावासों के माध्यम से प्रमाण पत्र सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी और शिकायतों के लिए एक तंत्र बनाना होगा। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन डिजिटल इंडिया और आधार जैसी सुविधाओं से इसे संभव बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, माता-पिता एक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं या दूतावास में जमा कर सकते हैं।

लिव-इन में दहेज कानून से संरक्षण की आस

डॉ. रितु सारस्वत

हाल ही में देश को शीर्ष अदालत ने 'लोकेश बी.एच. एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य' के मामले के आपराधिक कानून से जुड़े प्रश्न पर विचार करने के लिए सहमति दी है। क्या किसी महिला के साथ विवाह जैसे संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) में रहने वाले पुरुष को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत क्रूरता के अपराध के लिए अभियोजन के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं। उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा एक विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के 18 नवंबर 2025 के निर्णय को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धारा 498ए उन मामलों में भी लागू हो सकती है जहां संबंध विवाह के समान प्रकृति का हो। गौरतलब है कि धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी महिला के साथ उसके पति अथवा पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है, तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा।

इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विवाहित महिलाओं को दहेज से जुड़े उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करते हुए उसे नोटिस जारी किया है और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले से संबंधित समस्त डिजिटल अभिलेख उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही, इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह प्रश्न सरल या एकरेखीय नहीं है। इसके एक पक्ष में स्त्री के अधिकार, गरिमा और सुरक्षा का संवेदनशील प्रश्न निहित है, तो दूसरे पक्ष में विधि की वह मर्यादा भी है जिसके अंतर्गत दहेज-निरोधक तथा क्रूरता संबंधी प्रावधानों को पारंपरिक रूप से वैध वैवाहिक संबंधों से जोड़कर देखा जाता है।

एक ओर लिव-इन संबंध भारतीय समाज में गाहे-बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं; वहीं दूसरी ओर, इनके साथ वे सभी जटिलताएं और विवाद भी सामने आ खड़े हो रहे हैं, जो प्राय: विधिसम्मत वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कानून मूलत: वैवाहिक संस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, उन्हीं प्रावधानों का आश्रय लेते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े कानून के दरवाजे खटखटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार, यह विमर्श केवल दंडात्मक कानून की तकनीकी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विधिक सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती भी है। सबसे अधिक विस्मयकारी पहलू यह है कि अनेक युवा तथाकथित आधुनिक जीवन-दृष्टि और स्वतंत्रता के आग्रह के साथ लिव-इन संबंधों में प्रवेश करते हैं, मानो वे सामाजिक तथा विधि-सम्मत परंपरागत व्यवस्थाओं को महत्व नहीं देते। परंतु जब विवाद या संकट उत्पन्न होता है, तो वही पक्ष उन कानूनी संरक्षणों की शरण में जाते दिखाई देते हैं, जो मूलत: पारंपरिक वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए थे।

यह विरोधाभास एक ओर सामाजिक मान्यताओं से विमुखता और दूसरी ओर उन्हीं से उपजे विधिक संरक्षण की अपेक्षा-कानून के समक्ष निरंतर एक नया संतुलन स्थापित करने की चुनौती उपस्थित कर रहा है। जनवरी, 2004 को 'रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम एवं अन्य के मामले' में देश की शीर्ष अदालत ने कहा 'धारा 498ए को लागू करने के लिए 'पति' शब्द के अंतर्गत कौन-कौन आएगा, यह प्रश्न वास्तव में जटिल है। शब्दार्थ की दृष्टि से, विभिन्न विधि शब्दकोशों और शब्दावली में 'पति' तथा 'विवाह' की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनसे यह प्रतीत हो सकता है कि दंडात्मक प्रावधान लागू करने के लिए वैध विवाह का अस्तित्व अनिवार्य शर्त है।' अदालत ने यह भी कहा कि 'दहेज' की अवधारणा मूलत: विवाह से जुड़ी होती है और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधान भी विवाह के संदर्भ में ही लागू होते हैं। यदि स्वयं विवाह की वैधता ही विवादित हो, तो इससे अतिरिक्त विधिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अजयनाथ बनाम केरल राज्य, में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 498ए के अंतर्गत अभियोजन चलाने के लिए अभियुक्त और पीड़िता के बीच वैध वैवाहिक संबंध होना अनिवार्य है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि कथित विवाह प्रारंभ से ही शून्य हो, तो धारा 498ए के अंतर्गत अभियोजन कायम नहीं रह सकता।

वर्ष 2003 के कलियापेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 498ए अथवा उससे संबंधित प्रावधान स्वत: लागू नहीं हो जाते; इनके लिए विधि द्वारा मान्य वैवाहिक संबंध का अस्तित्व आवश्यक है। यदि विवाह ही वैध न हो या दहेज से जुड़ा तत्व स्थापित न हो, तो आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता। इसी तर्क का विस्तार तथाकथित 'पति के संबंधियों' तक भी होता है। जब विधिक दृष्टि से 'पति' का दर्जा ही सिद्ध न हो, तो उसके संबंधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी स्वत: कमजोर पड़ जाती है। यही नहीं जुलाई, 2024 में केरल उच्च न्यायालय ने 'डॉ. अश्विन वी. नायर बनाम केरल राज्य एवं अन्य'में यह निर्णय दिया कि किसी महिला का लिव-इन पार्टनर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत 'पति' की परिभाषा में नहीं आता।

शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि खानपान में कम उम्र से ही सुधार कर लें। जिन लोगों का आहार ठीक नहीं रहता है उनमें पाचन में गड़बड़ी से लेकर कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का खतरा अधिक हो सकता है। जब भी बात खानपान में सुधार की होती है तो हम अक्सर विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की बात तो करते हैं, लेकिन शरीर के सही विकास और सुचारू कार्य के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम के महत्व को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि यही तत्व शरीर के अंदर सैकड़ों बायोकेमिकल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मैग्नीशियम हमारे शरीर की कई क्रियाओं जैसे हड्डियों को मजबूत रखने, मांसपेशियों के सही कार्य, नसों के सिग्नल, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और हार्टबीट को सामान्य बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, अनिद्रा जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं।

आहार में सुधार करना जरूरी

मैग्नीशियम के लिए फलियां, हरी सब्जियां, बादाम, चिया एवं कद्दू के बीज, ब्राउन राइस, केला और एवोकाडो को आहार में शामिल कर सकते हैं। अधिक कमी होने पर चिकित्सक से सलाह लें। मैग्नीशियम की कमी कैल्शियम और पोटैशियम के स्तर को भी प्रभावित कर सकती है। शरीर का लगभग 60 प्रतिशत मैग्नीशियम हड्डियों में जमा होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन-डी के साथ मिलकर हड्डियों को स्वस्थ बनाकर ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है। हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम का सेवन करना चाहिए। मैग्नीशियम मस्तिष्क के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में मैग्नीशियम का कम स्तर तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है।

मैग्नीशियम की कमी से शरीर में हो सकती हैं ये समस्याएं

मैग्नीशियम को कहा जाता है नेचुरल रिलैक्सर

भले ही आप पर्याप्त नींद लें या पौष्टिक भोजन खाएं, लेकिन अगर शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो एनर्जी लेवल कम ही महसूस होता है। मैग्नीशियम को नेचुरल रिलैक्सर भी कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क में उन न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है, जो नींद और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि इसकी कमी होने पर अनिद्रा, चिंता, बेचैनी और तनाव बढ़ने लगती है।

शरीर में दर्द और नींद की समस्या

गड़बड़ लाइफस्टाइल और खानपान में पोषक तत्वों की कमी के कारण अधिकांश लोगों में मैग्नीशियम की कमी देखी जा रही है। समय रहते अगर इसके लक्षणों पर ध्यान न दिया जाए तो आपकी दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी खनिज है। इसकी कमी से शरीर में अनेक समस्याएं हो सकती हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों को दुरुस्त रखने, हृदय गति को स्थिर रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और ऊर्जा के उत्पादन में मदद करता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने पर मांसपेशी में ऐंठन, दिल की अनियमित धड़कन, थकान, उच्च रक्तचाप, अवसाद, चिंता और नींद से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो दौरे भी पड़ सकते हैं।

हंसना मना है

बॉयफ्रेंड- मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड- तुम्हारे घर में कौन -कौन हैं? बॉयफ्रेंड - एक बीवी और तीन बच्चे।

कमलेश (मित्र श्याम से)- यार मेरी पत्नी तो एकदम पागल है। हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती है। परसों एक साड़ी लाने को कह रही थी। आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। श्याम-अजीब बात है। वह इतनी साड़ियों का क्या करती है? कमलेश- पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो दी नहीं।

एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया। लड़की-अपने अंकल को फोन दो, लड़का-वो तो बाथरूम में हैं, आपका नाम? लड़की-उनसे कहो कि उनकी जानेमन का फोन है, बच्चे ने कहा-लेकिन आंटी, मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है!

बीवी-अजी सुनते हो, खुशनसीब को इंग्लिस में क्या कहते हैं? पति-अनमैरिड, दे बेलन, दे चिमटा, दे फूकनी?

कहानी | मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी

एक बार की बात है किसी जंगल में एक कौआ रहता था। वह बहुत दुष्ट था इसलिए हर कोई उससे दूर ही रहता था, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज में गाता रहता था और सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकल कर आ गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी। जैसे ही कौआ रोटी खाने को हुआ, नीचे से लोमड़ी की आवाज आई - अरे कौआ महाराज, मैंने सुना है कि यहां पर बहुत सुरीली आवाज में कोई गाना गाता है, क्या वो आप हैं। लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौआ मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हां में हिला दिया। इस पर लोमड़ी बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज। इतनी मधुर आवाज में आप गा रहे थे, मैं यह कैसे मान लूं? अगर आप गा कर बताएंगे, तो मुझे यकीन हो जाएगा। कौआ लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहां से चली गई। भूखा कौआ लोमड़ी को देखता रह गया और अपने किए पर बहुत पछताया।

कहानी से सीख- इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए, जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं।

7 अंतर खोजें

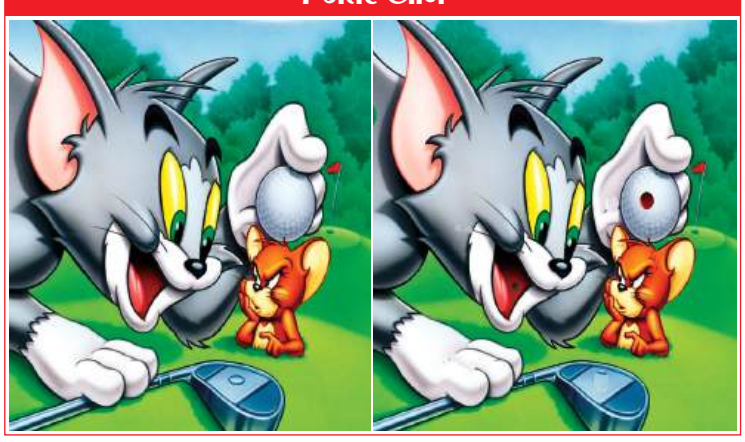

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कुसंगति व जल्दबाजी से बचें। विवेक से कार्य करें, लाभ होगा। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा।

वृषभ

कोर्ट व कचहरी के कार्यों में अनुकूलता रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। लाभ होगा। आर्थिक साधनों में बढ़ोतरी होगी।

मिथुन

संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। समय का सदुपयोग होगा। जल्दबाजी न करें। प्रवास में सावधानी रखें।

कर्क

स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। विवाद न करें। व्यापार में स्वयं के निर्णय से काम कर पाएंगे।

सिंह

मेहनत अधिक होगी। बुरी खबर मिल सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। पुराना रोग उभर सकता है। व्यापार, नौकरी में स्थिति मध्यम रहेगी।

कन्या

मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में गति आएगी।

तुला

पुराने मित्र व संबंधी मिलेंगे। अच्छे समाचार मिलेंगे। विवाद से बचें। मान बढ़ेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। परिवार में शांति का अनुभव होगा। धर्म में रुचि रहेगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। धनार्जन होगा। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। प्रसिद्ध व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा।

धनु

अप्रत्याशित खर्च होंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। वस्तुएं संभालकर रखें। आर्थिक स्थिति से ऋण की समस्या उभरेगी।

मकर

यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। बकाया वसूली होगी। आय में वृद्धि होगी। प्रसन्नता रहेगी। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति होगी।

कुंभ

कार्यस्थल पर सुधार होगा। नए अनुबंध हो सकते हैं। योजना फलीभूत होगी। धनार्जन होगा। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी।

मीन

पूजा-पाठ में मन लगेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। राजकीय सहयोग मिलेगा। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। अपनी भावनाओं को संयमित रखकर कार्य करें।

बाफ्ता अवॉर्ड के मंच पर जलवा बिखेरेंगी आलिया भट्ट

बॉलीवुड | गपशप

ब्रिटिश फिल्म अकादमी की तरफ से इस साल के पुरस्कारों का एलान बहुत जल्द किया जाएगा। कुछ दिन पहले बाफ्ता अवॉर्ड 2026 में नॉमिनेट हुई फिल्मों की लिस्ट को जारी किया गया था और अब अवार्ड प्रेजेंटर की सूची भी सामने आ गई है, जिसमें हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। 79वें बाफ्ता पुरस्कार में आलिया हॉलीवुड सिनेमा की तमाम हस्तियों के संग मंच शेयर कर करेंगी और भारतीय सिनेमा का नाम रोशन करेंगी। आइए जानते हैं कि वह कौन से दिग्गज हैं, जिनके साथ बाफ्ता अवार्ड प्रेजेंटर के तौर पर आलिया का नाम शामिल किया गया है।

22 फरवरी को बाफ्ता अवॉर्ड 2026 के विजेताओं का एलान किया जाएगा। इसके लिए ब्रिटिश फिल्म अकादमी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। मंगलवार को बाफ्ता की तरफ से अवार्ड प्रेजेंटर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें आलिया भट्ट एकमात्र भारतीय सेलेब्स मौजूद हैं। उनके अलावा हॉलीवुड सिनेमा के बड़े सुपरस्टार इस बार अवार्ड प्रेजेंटर के तौर पर बाफ्ता में मौजूद रहेंगे, जिनके नाम इस प्रकार हैं-ब्रायन क्रैन्स्टन, एरन पियरे, सिलियन मर्फी, एमी लू वुड, एलिसिया विकेंडर, नोआ जूप, ओलिविया कुक, पैट्रिक डेम्पसी, रेगे-जीन पेज, एथन हॉक, गिलियन एंडरसन, ग्लेन क्लोज, हन्नाह वाडिंगहैम, केट हडसन, कैथरीन हैन, केरी वाशिंगटन, लिटिल सिम्ज, मैगी गिलेनहाल, डेविड जोनसन, डेलरॉय लिंडो, एमिली वॉटसन, स्टॉर्मजी, वारविक डेविस, एरिन डोहर्टी, स्टेलन स्कारगार्ड, मिया मैककेना-ब्रूस, माइकल बी. जॉर्डन, माइल्स कैटन, मिली एल्कॉक, मिन्नी ड्राइवर, मोनिका बेलुची, सैडी सिंक और रिज अहमद शामिल हैं। मालूम हो कि आलिया भट्ट से पहले साल 2024 में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी बाफ्ता अवॉर्ड सेरेमनी में अवार्ड प्रेजेंटर की जिम्मेदारी को निभा चुकी हैं। इसका अलावा गौर करें आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म की तरफ तो उसका नाम लव एंड वॉर है, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं।

इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड्स बाफ्ता के 79वें संस्करण के लिए जिस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, उसका नाम बोंग है। साल 2024 में रिलीज होने वाली इस मूवी का डायरेक्शन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया, जबकि निर्माता की कमान फरहान अख्तर ने संभाली। बता दें कि ये एक ये मणिपुरी भाषा की एक ड्रामा मूवी है, जिसे बाफ्ता अवॉर्ड 2026 की बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है।

मर्दानी 4 में भी खाकी का दम दिखाएंगी रानी मुखर्जी

यशराज फिल्म्स की सफल फ्रेंचाइजी मर्दानी 3 को लंबे इंतजार के बाद रिलीज किया गया। कमर्शियल तौर पर रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या भविष्य में मेकर्स मर्दानी फ्रेंचाइजी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और चौथी किस्त लेकर आएंगे या नहीं। इस मामले को लेकर हाल ही में मर्दानी 3 के डायरेक्टर अभिराज मीनावाला ने खुलकर बात की है। आइए जानते हैं कि अभिराज ने मर्दानी 4 को लेकर क्या कहा है।

मर्दानी 3 की सफलता के बाद

हाल ही में निर्देशक अभिराज मीनावाला ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ खास बातचीत की है और इस दौरान उनसे मर्दानी 4 को लेकर भी जरूरी सवाल पूछा गया, जिस पर अभिराज ने कहा है- मेरे हिसाब से देखा जाए तो मर्दानी 4 जरूर बननी चाहिए। इतना ही नहीं कई ऐसी फिल्में भी हैं, जिनको जरूर बनना चाहिए। मर्दानी 1 और मर्दानी 2 ने हमें तीसरा पार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मर्दानी 2 को साल 2019 में रिलीज किया गया था और अब 7 साल बाद इसका तीसरा पार्ट आया है। मर्दानी 4 की मेकिंग के लिए सबसे अहम चीज ये है कि हमारे पास एक मजबूत स्क्रिप्ट और बेहतरीन कंटेंट स्टोरी होना अनिवार्य है।

इस तरह से अभिराज मीनावाला ने मर्दानी पार्ट 4 की मेकिंग को लेकर गोलमोल जवाब दिया है। उनके इस स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर होता है कि फ्यूचर में रानी मुखर्जी लेडी पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में कन्फर्म तौर पर नजर आ भी सकती हैं और नहीं भी।

बता दें कि मर्दानी फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। 30 जनवरी को रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। तब से लेकर अब तक इस मूवी ने कमाई के लिहाज से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। गौर करें मर्दानी 3 के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह 48 करोड़ के करीब पहुंच गया है।

बॉलीवुड | मन की बात

कभी हम बॉलीवुड बनना चाहते थे अब दुनिया हमें देख रही : निखिल

साउथ के लोकप्रिय अभिनेता निखिल सिद्धार्थ अपनी नई फिल्म 'स्वयंभू' के जरिए बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। इस इंटरव्यू में अभिनेता ने फिल्म, इसकी तैयारी और बॉलीवुड समेत कई मुद्दों पर बात की। 'कार्तिकेय 3' की योजनाओं पर खुलकर बात करते हुए उन्होंने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के फर्क पर भी अपनी राय रखी। फिल्म 'कार्तिकेय' से मुझे बहुत प्यार मिला। लोग मुझे मेरे असली नाम की जगह 'कार्तिकेय' नाम से ज्यादा जानते हैं। लोगों ने उस फिल्म को दिल से पसंद किया। उसी प्यार ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। फिल्म 'स्वयंभू' की यात्रा लगभग दो साल की रही। 'कार्तिकेय 2' के बाद से ही लोग मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं? घर पर बैठा हूं क्या? मेरा जवाब बस इतना ही था कि जब भी वापस आऊंगा, कुछ खास लेकर आऊंगा। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 180 दिनों तक चली। टीजर रिलीज के बाद से ही लोगों की प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुशी हुई। यह एक पीरियड फिल्म है। मैं इसमें एक छोटे से सैनिक की भूमिका निभा रहा हूं। इसके लिए मुझे तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी सब कुछ सीखना पड़ा। हम इसकी ट्रेनिंग के लिए वियतनाम गए थे। मेरे प्रोड्यूसर ने हमें एक शानदार जगह भेजा। वहां लगभग 40 मार्शल आर्टिस्ट ने मेरी ट्रेनिंग करवाई। फिल्म में कई बड़े दृश्य हैं। लगभग सौ सैनिक, सैकड़ों फाइटर्स, हजारों जूनियर आर्टिस्ट। इतने बड़े स्तर पर काम करने के लिए उसी स्तर की तैयारी जरूरी थी। मेरा बॉलीवुड के प्रति हमेशा सम्मान रहा है। पहले हम सोचते थे कि हमें बॉलीवुड जैसी फिल्में बनानी हैं। उनके जैसे टेक्नीशियन लाने हैं। उसी स्तर पर काम करना है पर अब स्थिति बदल चुकी है। दक्षिण भारत में मजबूत तकनीकी टीमें तैयार हो चुकी हैं। आज पूरी दुनिया भारतीय सिनेमा की ओर देख रही है। हालांकि, हाल के समय में मैं 'धुरंधर', 'एनिमल' और 'सैयारा' जैसी फिल्मों के तकनीकी काम से प्रभावित हुआ हूं।

30 लाख कुत्तों को मौत के घाट उतारने वाला है ये देश! वर्ल्डकप से पहले कर रहा तैयारी

2030 फीफा वर्ल्ड कप का संयुक्त आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को कर रहे हैं। फीफा ने अक्टूबर 2023 में इसकी घोषणा की थी और दिसंबर 2024 में इसे अंतिम मंजूरी मिली थी। टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन चौकाने वाली खबर सामने आई है। देश में अनुमानित 30 लाख (3 मिलियन) आवारा कुत्तों को मारने का प्लान चल रहा है, ताकि वर्ल्डकप के दौरान शहर 'साफ-सुथरे' और 'पर्यटकों के लिए सुरक्षित' दिखे। पशु अधिकार संगठनों और अन्य ने आरोप लगाया है कि मोरक्को सरकार ने कुत्तों की सामूहिक हत्या शुरू कर दी है। देश पर आरोप है कि वो कुत्तों को मार रहे हैं। ये तरीके बेहद क्रूर हैं, जिसमें जहर (स्ट्रिक्नाइन) खाने में मिलाकर या इंजेक्शन देकर, बंदूकों से गोली मारकर, नेक क्लैंप से पकड़कर ट्रकों में भरकर, फिर फेक डिस्पेंसरी में ले जाकर जिंदा जलाना या मास ग्रेव में फेंकना शामिल है। कई कुत्ते घायल होकर तड़पते रहते हैं, चीखते हैं, लेकिन मौत धीमी आती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बच्चे यह सब देखकर ट्रॉमा में हैं। मोरक्को में हर साल करीब 3 लाख कुत्ते मारे जाते थे, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से यह संख्या बढ़ गई है। शहरों जैसे माराकेश, फेज, इफ्रेन में 'क्लीन-अप' अभियान चल रहा है। इफ्रेन के टूरिज्म काउंसिल प्रेसिडेंट ने CNN को बताया कि वर्ल्ड कप के लिए सड़कों से कुत्तों को हटाया जा रहा है। मोरक्को में स्ट्रे डॉग्स की समस्या पुरानी है। हर साल 1 लाख कुत्ते के काटने की घटनाएं होती हैं। लेकिन पशु अधिकारियों का कहना है कि कटाई लंबे समय तक समस्या हल नहीं करती। इसके बजाय Trap-Neuter-Release (TNR) प्रोग्राम अपनाना चाहिए, जहां कुत्तों को पकड़कर नसबंदी, वैक्सीनेशन कर वापस छोड़ दिया जाए। मोरक्को ने 2024 में TNR का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे छोड़कर क्रूर तरीके अपनाए गए हैं। वहीं इसे लेकर मोरक्को सरकार और एम्बेसी ने आरोपों से इनकार किया है। लंदन एम्बेसी ने कहा कि देश ह्यूमेन एनिमल मैनेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध है और कटाई पर बैन है। लेकिन पशु संगठनों ने 91-पेज का डोजियर फीफा को सौंपा है, जिसमें फोटो, गवाही और सबूत हैं। PETA ने प्रोटेस्ट किया और मैच में घुसकर पोस्टर दिखाए। मार्क रफालो जैसे सेलेब्रिटी ने भी सोशल मीडिया पर कैंपेन को सपोर्ट किया है। यह घटना बीजिंग ओलंपिक्स 2008 और सोची ओलंपिक्स जैसी पुरानी घटनाओं की याद दिलाती है, जहां भी बड़े इवेंट से पहले स्ट्रे एनिमल्स को मारा गया था। पशु प्रेमी फीफा से मांग कर रहे हैं कि मोरक्को को जवाबदेह बनाया जाए, अन्यथा होस्टिंग रद्द की जाए। फीफा का कहना है कि वे ह्यूमन राइट्स का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है।

अजब-गजब | दुनिया का सबसे नमकीन तालाब

-58 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी नहीं जमता यहां का पानी!

आप ये तो जानते होंगे कि समुद्र में नमक होता है। नमक मिलने की वजह से उनका घनत्व, नदी या तालाब की तुलना में ज्यादा होता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी तालाब है जिसके पानी का घनत्व इतना ज्यादा है कि -58 डिग्री तक तापमान पहुंचने के बाद भी पानी नहीं जमता। यही नहीं, इसका घनत्व डेड सी से ज्यादा है। ये अनोखा तालाब अंटार्कटिका में मौजूद है। आइए, आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं।

अंटार्कटिका के मैकमुर्डोज ड्राय वैली में मौजूद एक तालाब, डॉन जुआन दुनिया का सबसे नमकीन पानी का स्रोत है। इसका पानी डेड सी से भी ज्यादा नमकीन है। यही कारण है कि जब तापमान -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब भी ये तालाब नहीं जमता। ये तालाब करीब 4 इंच गहरा है। ये असल में तालाब कम और बड़ा गड्डा ज्यादा लगता है। पर इस तालाब ने वैज्ञानिकों को सालों से हैरान किया है। कारण है इसकी अनोखी संरचना। साल 1961 में वैज्ञानिकों ने इस तालाब की खोज की थी।

तब वो ये देखकर हैरान हुए थे कि जिस जगह पर मौसम का तापमान -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उस जगह पर

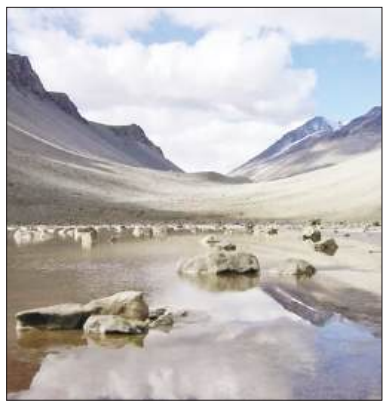

पानी का ये छोटा सा स्रोत नहीं जम रहा था। उसी वक्त उस तालाब की जांच की गई और पाया गया कि उस तालाब के पानी में 40 फीसदी नमक मिला है। तुलना के लिए बता दें कि डेड सी में नमक की मौजूदगी 34 पर्सेंट है। वहीं दुनिया के तमाम महासागरों का पानी 3.5 पर्सेंट तक नमकीन है और ग्रेट सॉल्ट लेक में 5 से 26 फीसदी तक नमक है। हैरानी की बात ये है कि ये तालाब धरती की सबसे सूखी जगहों में से एक, मैकमुर्डोज़ ड्राय वैली में है। यहां पर शायद ही कभी बारिश होती होगी। ये बिल्कुल सूखी जगह है, जहां पर 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। हैरानी ये भी है कि अंटार्कटिका में होने के बावजूद यहां पर बर्फ नहीं पड़ती।

इस जगह के आसपास के तालाब ठंड में जम जाते हैं और उनके ऊपर मोटी बर्फ जम जाती है। पर डॉन जुआन पॉन्ड शायद ही कभी जमता होगा। इसका कारण है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे कर देता है और बर्फ नहीं जमने देता। सालों तक वैज्ञानिकों को यही लगता रहा कि ये तालाब ग्राउंडवॉटर से भरा है, जो नीचे आ रहा है। पर 10 साल पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खोजा कि ये नमकीन पानी अधिकतर हवा से आता है। उन्होंने कैमरे लगाकर ये दिखाया कि मिट्टी में जो नमक मौजूद है, वो हवा से नमी को सोखता है। इस प्रोसेस को तरलीकरण कहते हैं। ये नमकीन पानी फिर धीरे-धीरे तालाब में जाने लगता है और पिघली हुई बर्फ के साथ मिल जाता है। सबसे रोचक बात ये भी है कि वैज्ञानिकों को इतनी दुर्गम स्थिति में भी जीव-जंतुओं के सबूत मिले हैं। इस वजह से उनका मानना है कि अगर यहां पर जीवन होने की संभावना है तो फिर मार्स ग्रह पर भी होगी, जहां की परिस्थितियां यहां के जैसी ही हैं।

गठबंधन में राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय की कमी : राउत

» चुनाव नजदीक आने पर ही सक्रिय होते हैं इंडिया ब्लॉक के नेता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने विपक्षी दल के इंडिया ब्लॉक के कामकाज की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर ही सक्रिय होता है और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार समन्वय का अभाव रहता है। राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का काम चुनाव नजदीक आने पर ही शुरू होता है। तब तक किसी के बीच कोई संवाद नहीं होता। तब तक इंडिया ब्लॉक में जनता क्या कर रही है, यह किसी को नहीं पता होता। संसद के अंदर मुद्दों को उठाना ही काफी नहीं है, खासकर तब जब विपक्षी नेताओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने तक नहीं देते।

क्या हम बाहर कुछ कर सकते हैं? राउत ने तर्क दिया कि गठबंधन को पूरे राजनीतिक चक्र में सक्रिय रहना चाहिए, न कि केवल आम चुनाव से पहले। उन्होंने किसानों की परेशानी, कानून व्यवस्था और मणिपुर की स्थिति सहित कई गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया, जिन पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, अमेरिका के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप देश के किसान मरेंगे, आत्महत्या करेंगे और भुखमरी से मरेंगे। लेकिन सिर्फ संसद में आवाज उठाने से भारत गुट को कोई फायदा नहीं होगा।

गठबंधन की एक औपचारिक बैठक बुलाई जाए

गठबंधन के भीतर संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चाओं पर राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसे नेताओं को ब्लॉक का नेतृत्व करने के सुझाव व्यक्तिगत राय हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना है, तो गठबंधन की एक औपचारिक बैठक बुलाई जानी चाहिए। 2026 में, भारत के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन पांच विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं, वे हैं बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी।

हमें सतर्क रहने की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि गठबंधन को सतर्क रहना चाहिए और अपने घटक दलों के बीच नियमित संचार सुनिश्चित करना चाहिए। राउत ने कहा कि महीनों, यहां तक कि सालों तक वे किसी से बात नहीं करते। चाहे उद्धव ठाकरे हों या अन्य नेता, हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक न केवल लोकसभा चुनावों से पहले, बल्कि उससे भी पहले सक्रिय रहे।

मध्य प्रदेश के बजट पर सियासी घमासान, भाजपा ने किया बखान

» बजट यथार्थवादी होना चाहिए: कांग्रेस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2026-27 के राज्य बजट पर बोलते हुए समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए किए गए आवंटनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार पर केंद्रित है। हमने 2047 तक एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। हमने जर्जर पुलों और पुलियों की मरम्मत के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 2028 के सिंहस्थ महोत्सव के लिए लगभग 13,851 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मोहन यादव ने कहा कि हमने स्कूलों में बच्चों को भोजन के साथ दूध उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है और सरकार ने इसके लिए पांच वर्षों में 6,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हम कोई भी योजना बंद नहीं कर रहे हैं, हम पर्याप्त धनराशि निवेश कर रहे हैं। वीबी-जी-राम-जी के लिए 28,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह बजट एक खुशहाल और समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के कारण राज्य की आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है और इस वर्ष लगभग 72,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 532,000 करोड़ रुपये के ब्याज सहित देनदारियां बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जो एक गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर रही हैं। बजट यथार्थवादी होना चाहिए।

बजट खोखला और बेबुनियाद है : पटवारी

पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश के बजट में लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में हमें केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपये नहीं मिले। परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार 2025-26 के बजट का 50प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि बजट खोखला और बेबुनियाद है।

भारत की विश्वकप में लगातार 12वीं जीत

» शिवम दुबे चमके, नीदरलैंड को 17 रनों से हराया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अहमदाबाद। शिवम दुबे की शानदार बल्लेबाजी के बाद वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी के दम पर भारत ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराया। गत चैंपियन भारतीय टीम ने इस तरह ग्रुप चरण का अंत अजेय रहते हुए किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम निर्धारित ओवर में सात विकेट पर 176 रन ही बना सकी। भारत ने टी20 विश्वकप में लगातार 12वीं जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में भारत 2024 से ही अजेय बना हुआ है।

भारतीय टीम भले ही मैच जीतने में सफल रही, लेकिन उसकी फील्डिंग एक बार फिर खराब रही। भारत के लिए नीदरलैंड के खिलाफ मैच में सूर्यकुमार और तिलक वर्मा ने कैच छोड़े। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी में भी टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और एक बार फिर बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। शिवम दुबे ने हालांकि, शानदार बल्लेबाजी की जिस कारण टीम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे सकी। वरुण चक्रवर्ती के फिरकी के जादू से भारत ने नीदरलैंड को हराया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे नीदरलैंड ने धीमी शुरुआत करते हुए पावरप्ले में एक विकेट पर 36 रन बनाए। नोह क्रोस तथा जैक लियोन कैशे ने सातवें विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। शिवम दुबे ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 31 गेंद में छह छक्कों और चार चौकों से 66 रन की पारी खेली। शिवम ने हार्दिक पांड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की।

विश्वकप में अभी तक नहीं खुला अभिषेक का खाता

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म नीदरलैंड के खिलाफ भी जारी रही। अभिषेक एक बार फिर खाता खोले बिना आउट हुए और सिर्फ तीन ही गेंद खेल सके। अभिषेक की फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है क्योंकि अब टीम को आगे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा टूर्नामेंट में अभिषेक अब तक खाता भी नहीं खोल सके हैं क्योंकि अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में अभिषेक शून्य पर आउट हुए थे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ वह खाता नहीं खोल पाए थे और अब नीदरलैंड के खिलाफ भी उनका बला खामोश ही रहा। अभिषेक पेट में संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ दूसरे मैच से बाहर रहे थे। अभिषेक ने पिछली सात पारियों में एक अर्धशतक लगाया है। उन्होंने 0, 68*, 0, 30, 0, 0 और 0 रन बनाए हैं। यानी पिछली सात पारियों में अभिषेक के बल्ले से सिर्फ एक बार अर्धशतक निकल रहा है और कुल 98 रन ही बना सके हैं। इतना नहीं सात में से पांच बार तो वह खाता भी नहीं खोल सके हैं।

कब्जे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर स्थित घाटा संख्या 632 की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। करोड़ों रुपये मूल्य की इस ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच नगर निगम ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है।

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित लेखपाल को कब्जाधारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर लेखपाल अजीत तिवारी ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तहरीर दी है। गौरतलब है कि ग्राम हरिहरपुर की खसरा/घाटा संख्या 632 सहित अन्य ग्राम समाज की जमीनों पर फर्जी पट्टों के माध्यम से अवैध प्लाटिंग और निर्माण कराए जाने के आरोप पहले ही सामने आ चुके हैं। इस प्रकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी प्रशासन से शिकायत की गई थी। आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी जमीन को कथित रूप से गलत तरीके से भूमिधर दर्ज कराकर बाजार में बेचे जाने की कोशिश की गई। मामले के तूल पकड़ने और 4पीएम अखबार खबर प्रमुखता से उठने के बाद प्रशासन हरकत में आया। नगर आयुक्त के निर्देश पर जांच शुरू की गई और अब अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अवैध निर्माण पर कब तक प्रभावी कार्रवाई होती है और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाता है।

» अपर नगर आयुक्त ने अपनाया कड़ा रुख, लेखपाल ने दी तहरीर

वाणिज्यिक वाहनों पर वन टाइम रोड टैक्स की सुविधा शुरू

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गाजीपुर। परिवहन विभाग ने एक फरवरी से नई व्यवस्था लागू करते हुए 7500 किलो क्षमता से कम भार वाले वाणिज्यिक वाहनों पर वन टाइम रोड टैक्स की सुविधा शुरू कर दी है। अब ऐसे वाहन मालिकों को व्यक्तिगत वाहनों की तरह एकमुश्त टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें 15 वर्षों तक अलग से रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

अब तक छोटे-बड़े लगभग सभी वाणिज्यिक वाहनों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य था, जिससे वाहन मालिकों को बार-बार विभागीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह जानकारी एआरटीओ धनबीर यादव ने दी। यादव ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से छोटे वाहन संचालकों को प्रशासनिक झंझट और समय की बचत होगी। माना जा रहा है कि वन टाइम टैक्स की दरें लगभग चार साल के टैक्स के बराबर निर्धारित की गई हैं।

जय पवार ने बारामती प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल

» अजित के छोटे बेटे बोले - ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पुणे। पिछले महीने एक विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार ने दुर्घटना के पीछे गंभीर चूक होने की आशंका को लेकर गहन जांच की मांग की और कहा कि विमान का ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। इसी विमानन कंपनी के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

जय पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र के लोगों को दुर्घटना की पारदर्शी और पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। वीएसआर विमानन कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा, विमानन कंपनी की गंभीर चूक की आशंका और अनियमितताओं की विस्तृत व निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। उनका यह बयान महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राकांपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और विमान दुर्घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग के एक दिन बाद आया है। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने कहा कि घातक दुर्घटना वाले लीयरजेट 45 विमान के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) से डेटा प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता मांगी गई है।

गलगोटियास यूनिवर्सिटी की करतूत पर सियासी बवाल

विपक्ष ने भाजपा व एनडीए सरकार पर किया प्रहार, कांग्रेस, आप व शिवसेना यूबिटी ने उठाए सवाल

» आप बोली- बीजेपी सरकार शुरू से ही कॉपी-पेस्ट मॉडल चला रही है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटियास यूनिवर्सिटी रोबोडॉग ने जिस भारत की साख का गला घोटा है उसके बाद देश में सियासी बवंडर आ गया है। विपक्ष ने इस बदनामी के लिए भाजपा व केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एक्स पर एक पोस्ट में आप ने इस घटना को धोखाधड़ी बताया और कहा कि इससे भारत की वैज्ञानिक साख को नुकसान पहुंचा है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटियास यूनिवर्सिटी रोबोडॉग विवाद को लेकर बीजेपी पर अपना हमला तेज़ कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस घटना ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शर्मिंदा किया है। एक्स पर एक पोस्ट में आप ने इस घटना को धोखाधड़ी बताया और कहा कि इससे भारत की वैज्ञानिक साख को नुकसान पहुंचा है। आप ने कहा कि बीजेपी सरकार शुरू से ही कॉपी-पेस्ट मॉडल चला रही है। सूत्रों ने बताया कि दिन में पहले, अधिकारियों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो खाली करने को कहा है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर चीन में बने रोबोटिक कुत्ते को अपनी खोज बताकर दिखाया था। रोबोट को एग्ज़िबिशन में देखे जाने के बाद यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन और ऑफलाइन कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

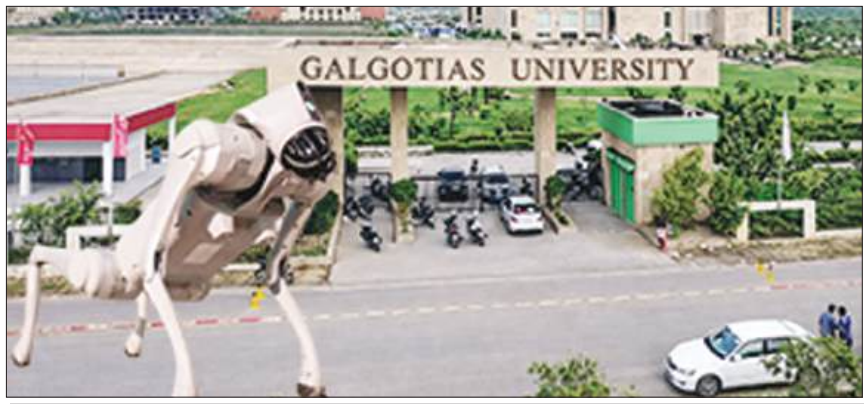

बिना सोचे-समझे पीआर तमाशा : राहुल गांधी

बढ़ते विवाद के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस इवेंट को एक बिना सोचे-समझे पीआर तमाशा बताया, जहाँ चीनी प्रोडक्ट्स के साथ भारतीय डेटा दिखाया जा रहा है। एक्स पर बात करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि भारत के टैलेंट और डेटा का फ़ायदा उठाने के बजाय, एआई समिट एक बेतरतीब पीआर तमाशा है - भारतीय डेटा बिक्री के लिए है, चीनी प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं।

सरकार 'रील मिनिस्टर' अश्विनी वैष्णव की देखरेख में कर रही है एआई समिट

अब सरकार 'रील मिनिस्टर' अश्विनी वैष्णव की देखरेख में एआई समिट कर रही है। इस दौरान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चीन से एक रोबोट डॉग लाई और उसे अपनी रिसर्च बताकर पेश कर दिया। इस धोखाधड़ी की वजह से भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर दुनिया भर में मज़ाक का विषय बन रहे हैं।

देश का अपमान कराने वालों को मिले सख्त सजा : प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (यूबिटी) एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई इम्पैक्ट समिट में कथित तौर पर चीन में बने रोबोटिक कुत्ते को अपना आविष्कार बताकर पेश किया, जिससे देश और समिट को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, चतुर्वेदी ने यूनिवर्सिटी पर सख्त सज़ा लगाने की मांग की। उन्होंने समिट आयोजित करने के लिए केंद्र की भी आलोचना की और कहा कि अगर कंपनियों, यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप को पवेलियन देने से पहले उनकी क्रेडिबिलिटी की पूरी तरह से जांच की गई होती, तो इस विवाद से बचा जा सकता था। उद्धव गुट की सांसद ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एआई समिट में चीनी रोबोट को अपना आविष्कार बताना शर्म की बात है। चीनी मीडिया का इस पर खूब मज़ाक उड़ाना इसे और भी बुरा बनाता है। अगर पवेलियन देने से पहले कंपनियों/यूनिवर्सिटी/स्टार्टअप और दूसरों की क्रेडिबिलिटी अच्छी तरह चेक की जाती तो यह सब टाला जा सकता था। इससे भारत और समिट को बहुत नुकसान हुआ है, जबकि उनसे पवेलियन खाली करने के लिए कहा जाना एक अच्छा कदम है, मुझे लगता है कि उन पर कोई सख्त पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए।

कोर्ट की भी नहीं मान रहा चुनाव अयोग : अभिषेक बनर्जी

» तृणमूल कांग्रेस सांसद ने आयोग को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने एकबार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होने आरोप लगाया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करते समय भारत निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है।

बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग औपचारिक, निगरानी योग्य और जवाबदेह तंत्रों के बजाय व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश भेज रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा सकता है? देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और संचार के आधिकारिक माध्यमों के पालन पर जोर दिया है। फिर

भी हम देख रहे हैं कि निर्देश औपचारिक, पता लगाने योग्य और जवाबदेह तंत्रों के बजाय व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें हैं कि ईसीआई अधिकारी, विशेष रूप से विशेष रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन, अन्य अधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्रों को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दे रहे हैं ताकि हटाए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ाई जा सके। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि विशेष रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में माइक्रो ऑब्जर्वरों को सीधे जन्म प्रमाण पत्रों की स्वीकार्यता के संबंध में निर्देश जारी करने की विश्वसनीय रिपोर्टें हैं, ताकि हटाए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ाई जा सके। क्या मुझे ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट के उस स्पष्ट निर्देश की याद दिलाने की आवश्यकता है कि माइक्रो ऑब्जर्वरों की भूमिका केवल सहायक ही रहनी चाहिए? फिर वैधानिक प्रक्रिया को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, और किसके निर्देशों पर?

एक्स पोस्ट में आगे लिखा था।टीएमसी नेता ने व्हाट्सएप संदेशों के कथित स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिनमें अधिकारी कथित तौर पर दस्तावेज़ों की स्वीकार्यता के संबंध में निर्देश दे रहे हैं। लॉगिन डेटा का दुरुपयोग क्वेरी उत्पन्न करने और दिल्ली में ईसीआई के राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर एक विशेष समुदाय को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। यदि इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए, तो यह स्थापित हो जाएगा।

'घूसखोर पंडत' के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में वापस लिया फिल्म का टाइटल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब निर्माता नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया है। नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म का नया शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि हमने घुसखोर पंडित का शीर्षक और प्रचार सामग्री वापस ले ली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीरज पांडे द्वारा घुसखोर पंडित का शीर्षक वापस लेने संबंधी हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया और फिल्म के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया। शीर्ष न्यायालय में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए नीरज पांडे ने कहा कि फिल्म किसी भी धर्म या समुदाय का अपमान नहीं करती या उन्हें निशाना नहीं

बनाती है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि न तो मेरा और न ही मेरे प्रोडक्शन हाउस का भारत के किसी भी नागरिक की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादा था। फिल्म किसी भी माध्यम से किसी भी धर्म, समुदाय या धार्मिक मान्यताओं का अपमान नहीं करती है।

मुफ्त उपहारों की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा : सुप्रीम कोर्ट

» सरकार की रेवड़ी संस्कृति पर बिफरी अदालत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, तमिलनाडु बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है। वहीं एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की है।

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त उपहारों की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा ज्यादातर राज्य पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी विकास को छोड़कर मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा- जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें सहायता देना समझ में आता है। लेकिन अमीर-गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। इस दौरान कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली मिलती रही तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाएगी।

भाजपा ने दिया एकनाथ शिंदे को झटका!

भिवंडी महानगरपालिका में कांग्रेस के साथ मिलकर बना लिया मेयर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र की भिवंडी में अलग ही सियासत शुरू हो गई है. भिवंडी महानगरपालिका में कुछ ऐसा हुआ है जो महाराष्ट्र राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था. यहां पर मेयर पद का चयन करने के लिए दो बड़े विरोधी दल कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गए हैं।

दरअसल, भिवंडी मेयर पद के बीजेपी उम्मीदवार को कांग्रेस ने समर्थन दिया है. इसके लिए पार्टी ने पत्र लिखकर बाकायदा आधिकारिक रूप से अपने समर्थन का ऐलान किया। बीजेपी ने फैसला लिया है कि वह मेयर के लिए सेक्युलर उम्मीदवार के साथ जाएगी. इसलिए पद के लिए स्नेहा

पाटील का नाम दिया गया है। बता दें, पहले बीजेपी के उम्मीदवार नारायण चौधरी थे, लेकिन अब नया नाम स्नेहा पाटील का है. कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया है. लोकसभा सांसद अनिल देसाई ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए इस सियासी घटनाक्रम को आश्चर्यजनक बताया था। अब सवाल उठता है कि क्या भिवंडी की सत्ता से एकनाथ शिंदे को दूर करने के लिए बीजेपी ने कोई नई चाल चली है?

महानगरपालिका चुनाव के नतीजे

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका के चुनाव 15 जनवरी को हुए थे, जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए थे। भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस पार्टी को सबसे अधिक 30 सीटें मिली थीं। उसके बाद बीजेपी को 22 सीटें मिलीं। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 12, शरद पवार गुट की एनसीपी-एसपी 12, समाजवादी पार्टी को 6, कोनार्क विकास अघाड़ी को 4 और भिवंडी विकास अघाड़ी को 3 सीटों पर जीत मिली थी. यहां एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत हासिल हुई थी।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा